**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1188

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए कॉल सेन्टर और**

**मोबाइल ऐप्लीकेशन प्रारंभ करना**

1188. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः

 क्या मानव संसाधनविकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार अगले कुछ महीनों के दौरान समर्पित कॉल सेन्टर और मोबाइल ऐप्लीकेशन प्रारंभ करने के लिए एकदम तैयार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे विदेशी विद्यार्थी आकर्षित होंगे;

(ग) क्या सरकार विभिन्न देशों से विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अनेक अन्य उपाय भी कर रही है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में अगले दो वर्षों के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): भारत में रहने वाले विदेशी विद्यार्थियों के आने की गति को बढ़ाने और उनके लिए चुनिंदा स्‍थान/शिक्षा हब के रूप में भारत की रिब्रांडिंग करने के लक्ष्‍य को लेकर दिनांक 18.04.2018 को प्रारंभ किए गए भारत में अध्‍ययन नामक कार्यक्रम के तहत, एक समर्पित कॉल सेंटर दिसंबर, 2018 के अंत तक प्रारंभ किया जाना है। भारत में अध्‍ययन नामक वेबसाइट की व्‍यापक विशेषताओं वाली मोबाइल ऐप्‍लीकेशन पर भी कार्य किया जा रहा है और इसे नए शैक्षिक सत्र से पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा।

(ग): भारत सरकार ने देश में विदेशी छात्रों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए विभिन्‍न कदम उठाए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने व्‍यवस्थित ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, सामाजिक मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के माध्‍यम से देश में आने वाले अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों के प्रवाह की वृद्धि के द्वारा भारत को विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक हब बनाने के उद्देश्‍य से 18.04.2018 को स्‍टडी इन इंडिया (एसआईआई) कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम चयनित 30 प्‍लस देशों से विदेशी छात्रों को आकर्षित करने पर जोर देता है। कार्यक्रम में अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों के लिए 100 प्रतिशत से 25 प्रतिशत सीमा में मेधावी विदेशी छात्रों को फीस माफी सहित किफायती दरों पर सीटें प्रस्‍तावित कर चयनित प्रसिद्ध भारतीय संस्‍थान/विश्‍वविद्यालयों की भागीदारी की परिकल्‍पना की गई है। एक केंद्रीकृत प्रवेश वेबपोर्टल (https://studyinindia.gov.in) विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु एकल विंडों के रूप में कार्य करता है। पहले राउंड में, वर्ष 2018-19 में 5000 विदेशी छात्रों को विभिन्‍न संस्‍थाओं में स्‍थान दिया गया है।

एमएचआरडी ने (अक्‍टूबर, 2018 में) एक अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन (एसपीएआरसी) योजना शुरू की है जिसका लक्ष्‍य राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय महत्‍व की समस्‍याओं के संयुक्‍त समाधान के लिए भारतीय संस्‍थाओं और 28 चयनित राष्‍ट्रों की विश्‍व श्रेष्‍ठ संस्‍थाओं के बीच शैक्षिक और शोध सहयोग की सुविधा द्वारा भारत की उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं के शोध इकोसिस्‍टम का सुधार करना है। एसपीएआरसी के अंतर्गत, इस संयुक्‍त अनुसंधान परियोजना में दीर्घ अवधि शोध और शिक्षण गतिविधियों के लिए छात्रों/संकाय सदस्‍यों को उनकी भागीदारी के लिए पर्याप्‍त प्रोत्‍साहन दिया जाता है। अधिक विवरण https://sparc.iitkgp.ac.in पर है।

हाल ही में, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 76 शैक्षिक संस्‍थाओं (26.07.2018 के आंकड़ों के अनुसार) को स्‍वायत्‍तता दी है जिन्‍होंने उच्‍च शैक्षिक मानकों को बनाए रखा है। यूजीसी ने विश्‍वविद्यालयों को तीन श्रेणी में बांटा है: श्रेणी-।, श्रेणी-।। और श्रेणी-।।।. श्रेणी-। और श्रेणी-।। के तहत आने वाले विश्‍वविद्यालय यूजीसी के अनुमोदन के बिना उनकी स्‍वीकृत संकाय संख्‍या से अधिक 20 प्रतिशत तक विदेशी संकाय को रख सकते हैं। ये संस्‍थान विदेशी विद्यार्थियों को मेरिट आधार पर प्रवेश देने के लिए स्‍वतंत्र होंगे, जोकि घरेलू विद्यर्थियों की अनुमोदित संख्‍या से अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में 6 ऐसे संस्‍थाओं को उत्‍कृष्‍टता संस्‍थान का दर्जा प्रदान किया गया है। इन्‍हें अधिक स्‍वायत्‍ता देने का प्रावधान किया गया है अर्थात प्रवेश पाए विद्यार्थियों के 30 प्रतिशत तक विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देना; संकाय संख्‍या के 25 प्रतिशत तक विदेशी संकाय की भर्ती करना; बिना प्रतिबंध के विदेशी छात्रों की फीस निश्चित करना; और वसूल करना, क्रेडिट घंटों के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना तथा डिग्री प्राप्ति वर्षों को लचीला बनाना; पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करने में पूर्ण लचीलापन बरतना है।

आईआईटी में विदेशी विद्यार्थियो को आकर्षित करने के लिए, विदेश के छ: केन्‍द्रों एडिस अबाबा (इथोपिया), काठमाण्‍डू (नेपाल), सिंगापुर, दुबई (संयुक्‍त अरब अमीरात), ढ़ाका (बांगलादेश) और कोलंबो (श्रीलंका) में संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा, जेईई (एडवांस्‍ड) परीक्षा आयोजित की जा रही है। विदेशी छात्रों के लिए उपलब्‍ध अधिसंख्‍य सीटें प्रत्‍येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों की संख्‍या का अधिकतम 10 प्रतिशत तक उपलब्‍ध है जिन्‍हें जेईई (मेन) परीक्षा में शामिल हुए बिना सीधे तौर पर जेईई (एडवांस्‍ड) में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इसी तरह, आईआईटी और अन्‍य केन्‍द्रीय निधि प्राप्‍त प्रौद्योगिकी संस्‍थानों में एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ग्रेजुएट एप्‍टी‍ट्यूड टेस्‍ट फॉर इंजीनियरिंग (गेट) प्रवेश परीक्षा भी इन विदेशी केन्‍द्रों पर आयोजित की जाती है।

भारत सरकार की अन्‍य पहलों में स्‍टडी वेब्‍स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्‍पायरिंग माइंड्स (स्‍वयम), स्‍वयम प्रभा, राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उन्‍नत भारत अभियान (यूबीए), इम्‍पेक्‍टफुल पालिसी रिसर्च इन सोशल साइंस (इम्‍परेस), इम्‍पेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्‍नालॉजी (इम्प्रिंट), लीडरशिप फार एकेडेमिशियन प्रोग्राम (लीप), एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (अर्पित), नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी (एनएडी), नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (एनडीएल) आदि शामिल हैं। भारत सरकार की इन पहलों के अतिरिक्‍त यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा देश की उच्‍च शिक्षा गुणवत्‍ता मानक सुधार हेतु विभिन्‍न विनियम जारी किए गए हैं। राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन एवं प्रत्‍यायन परिषद (एनएएसी) और राष्‍ट्रीय प्रत्‍यायन बोर्ड (एनबीए) देश में उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करती है। इन पहलों का एक लाभ यह है कि भारत में उच्‍चतर शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए ज्‍यादा विदेशी छात्र आते हैं।

(घ) : स्‍थायी वित्‍त समिति ने अपनी दिनांक 15.03.2018 की बैठक में भारत में अध्‍ययन नामक कार्यक्रम के लिए शैक्षिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए 150 करोड़ के बजट को अनुमोदित किया है।

**\*\*\*\*\***